लोक सभा अध्यक्ष ने शिलांग में मेघालय और अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों के स्थानीय निकायों के लिए आउटरीच और परिचय कार्यक्रम का उद्घाटन किया

....

लघु विधायी निकायों के रूप में कार्य करने वाली जिला परिषदों को कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए : लोक सभा अध्यक्ष

...

एक्ट ईस्ट नीति से उत्तर-पूर्व क्षेत्र के विकास की अपार संभावनाओं के द्वार खुले हैं : श्री ओम बिरला

...

श्री बिरला ने स्थानीय निकायों के प्रशासन को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए सूचना और संचार तकनीकों तथा नई प्रौद्योगिकियों का अधिकाधिक उपयोग किए जाने पर बल दिया

...

लोक सभा अध्यक्ष ने लोकतांत्रिक संस्थाओं के सभी भागीदारों से सकारात्मक चर्चा और संवाद के माध्यम से सभी समस्याओं का समाधान करने का आग्रह किया

...

हमें अपने विचारों और कार्यों में राष्ट्रीय एकता के मूलभूत आदर्श को प्राथमिकता देनी चाहिए : मुख्य मंत्री, मेघालय

शिलांग 26 फरवरी 2021 : लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला 25 फरवरी 2021 को शिलांग पहुंचे और आज उन्होंने मेघालय और अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों के स्थानीय निकायों के लिए आउटरीच और परिचय कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

मेघालय के मुख्य मंत्री, डॉ कॉनरेड के संगमा; केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री, रामेश्वर तेली; मेघालय विधान सभा के अध्यक्ष, श्री मेतबाह लिंगदोह; मेघालय सरकार के जिला परिषद कार्य विभाग मंत्री, श्री लखमन रिम्बुई भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कार्यपालिका की जवाबदेही केवल संसद और विधान सभाओं में ही नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर भी सुनिश्चित की जाए। इस संबंध में श्री बिरला ने इस बात पर बल दिया कि लघु विधायी निकायों के रूप में कार्य करने वाली स्वायत्त जिला परिषदों को चर्चा और संवाद के माध्यम से कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए।

श्री बिरला ने कहा कि 'वोकल फॉर लोकल' जैसी पहलों से स्थानीय क्षेत्रों का विकास होगा । उन्होंने यह भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी साकार होगा जब हम वोकल फॉर लोकल का चुनाव करेंगे। महात्मा गांधी की संकल्पना का स्मरण करते हुए, लोक सभा अध्यक्ष ने कहा कि जब प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर होगा, तभी भारत आत्मनिर्भर होगा। अध्यक्ष महोदय ने यह भी कहा कि हमारी एक्ट ईस्ट नीति से उत्तर- पूर्व क्षेत्र के विकास की अपार संभावनाओं के द्वार खुले हैं और उत्तर पूर्वी राज्यों को इन अवसरों का अधिकाधिक लाभ उठाना चाहिए।

श्री बिरला ने स्थानीय निकायों के प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और सुगम बनाने के लिए सूचना और संचार तकनीकों और नई प्रौद्योगिकियों के अधिकाधिक उपयोग पर बल दिया। अध्यक्ष महोदय ने यह भी कहा कि पंचायती राज संस्थाएं समावेशी विकास की अवधारणा के साथ विकास कार्यक्रमों के संबंध में सहयोग और सामूहिकता की भावना से चर्चा करे तथा जनता की समस्याओं का समाधान जनता को केन्द्र में रखकर निकालें।

क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए श्री बिरला ने कहा कि हमारे लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं के भागीदारों से सकारात्मक चर्चा और संवाद के माध्यम से सभी समस्याओं का समाधान करने का आग्रह किया।

यह टिप्पणी करते हुए कि हमें अपने विचारों और कार्यों में राष्ट्रीय एकता के मूलभूत आदर्श को प्राथमिकता देनी चाहिए, मेघालय के मुख्य मंत्री, डॉ कॉनरेड के संगमा ने वित्त आयोग अंतरण के अंतर्गत जिला परिषदों का वित्तपोषण किए जाने; जिला परिषदों को दल-बदल विरोधी कानून के अंतर्गत लाए जाने; ख़ासी, गारो और अन्य भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने; उत्तर-पूर्वी जनजातियों और संस्कृति संबंधी जानकारी को स्कूली बच्चों के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने; और उत्तर-पूर्व में राष्ट्रपति आवास स्थापित किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन शिलांग में किए जाने तथा मेघालय और अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों के स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों को अपने अनुभव साझा करने का अवसर प्रदान करने के लिए लोक सभा अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया।

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री, श्री रामेश्वर तेली ने कहा कि पंचायत राज संस्थाएं और अन्य स्थानीय निकाय राष्ट्र-निर्माण के शक्तिशाली माध्यम हैं। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि जमीनी स्तर पर लोकतान्त्रिक प्रणाली को और सुदृढ़ करने के लिए लोकतन्त्र के परंपरागत मूल्यों का संरक्षण किया जाना चाहिए।

मेघालय विधान सभा के अध्यक्ष, श्री मेतबाह लिंगदोह ने स्व-शासन के महत्व पर बल देते हुए कहा कि इससे न केवल आम जनता सशक्त होगी बल्कि शासन को समाज के अंतिम व्यक्ति के द्वार तक पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। उन्होने निचले स्तर पर पंचायत राज संस्थाओं और स्वायत्त जिला परिषदों को सशक्त किए जाने पर ज़ोर दिया ताकि ऐसे निकायों की चर्चाओं में लोगों की शिकायतों और आकांक्षाओं पर भी विचार किया जा सके।

मेघालय सरकार के जिला परिषद कार्य विभाग मंत्री, श्री लखमन रिम्बुई ने कहा कि शासन की सशक्त लोकतान्त्रिक संस्थाएं विकास का आधार होती हैं । उन्होने यह आशा व्यक्त की कि यह आउटरीच कार्यक्रम मेघालय और अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों के स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा ।

उदघाटन समारोह के बाद निम्नलिखित विषयों पर पेनल चर्चाएँ हुईं : (i) भारत की संसद और जमीनी स्तर की संस्थाएं : संभावनाएं और चुनौतियाँ – नेतृत्व का प्रथम सोपान (ii) उत्तर-पूर्वी राज्यों में स्थानीय निकायों के नेतृत्व में जनजातीय कल्याण और (iii) उत्तर-पूर्वी राज्यों के प्राकृतिक संसाधन और इनके संरक्षण में स्थानीय और परंपरागत निकायों की भूमिका ।

मेघालय सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों के स्थानीय निकायों के लगभग 115 सदस्यों ने उपर्युक्त कार्यक्रम में भाग लिया । इसके अलावा सभी उत्तर पूर्वी राज्यों से अनेक प्रतिभागी वेबलिंक के माध्यम से ऑनलाइन इस कार्यक्रम में शामिल हुए ।

आज आयोजित समापन सत्र के बाद यह कार्यक्रम संपन्न हो गया ।

आउटरीच कार्यक्रम लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला की एक नई पहल है जिसका उद्देश्य पूरे देश में स्थानीय निकायों में सुशासन को बढ़ावा देना है । इस कार्यक्रम के माध्यम से निचले स्तर से शीर्ष स्तर तक विभिन्न स्तरों पर कार्यरत लोकतांत्रिक संस्थाओं द्वारा अपनाई जा रही पद्धतियों और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाकर लोकतंत्र में भागीदारी को बढ़ावा देने पर बल दिया जा रहा है। पहले आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन 8 जनवरी 2021 को देहरादून में किया गया था जिसमें 445 पंचायत प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और 40,000 पंचायत प्रतिनिधि और अधिकारी वेबलिंक के माध्यम से ऑनलाइन इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे ।

बाद में श्री बिरला ने प्रेस को संबोधित किया ।

इससे पहले, 25 फरवरी, 2021 को श्री बिरला ने मेघालय विधान सभा के सदस्यों को संबोधित किया । इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए, श्री बिरला ने कहा कि संसद से लेकर राज्यस विधानमंडलों और स्था नीय निकायों तक सभी संस्थाओं को आपसी समन्विय और सहभागिता से कार्य करना चाहिए और अपनी सर्वोत्तेम प्रक्रियाओं को एक-दूसरे के साथ साझा करना चाहिए। उन्हों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब हमारे कार्यों से समाज की अंतिम पायदान पर खड़े व्यिक्त का भला हो। उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि संवाद, वाद-विवाद और चर्चा से इस लक्ष्या को प्राप्ते किया जा सकता है।

कोविड-19 महामारी के दौरान लोक सभा में हुए विधायी कार्य के बारे में जानकारी देते हुए अध्यकक्ष महोदय ने कहा कि संसद ने महामारी के दौरान कार्य करके जनता को सकारात्महक संदेश दिया और उनका विश्वादस बढ़ाया। उन्होंने महामारी के दौरान मेघालय विधान सभा द्वारा निभाई गई सकारात्मक भूमिका की भी सराहना की ।

श्री ओम बिरला ने मेघालय विधान सभा के नए भवन के निर्माण स्थदल का दौरा भी किया। और इस संबंध में संसद की ओर से विधान सभा को सभी संभव सहायता और सहयोग दिए जाने का आश्वासन दिया ।